सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-31 अंक-16 22 अगस्त, 2016 | मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

कॉमरेड शिवदास घोष लाल सलाम

स्मृति दिवस पर 5 अगस्त को शिबपुर पार्टी सेण्टर में महान नेता कॉ. शिवदास घोष को लाल सलाम करते हुए पार्टी के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष

कॉमरेड फ्रेडरिक एंगेल्स लाल सलाम

कॉमरेड फ्रेडरिक एंगेल्स स्मृति दिवस पर 5 अगस्त को पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में लाल सलाम करते हुए पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड माणिक मुखर्जी

कॉमरेड शिवदास घोष स्मृति दिवस 5 अगस्त

देश भर में यथोचित सम्मान–क्रान्तिकारी अनुशासन–मर्यादा के साथ मनाया गया

सर्वहारा के महान् नेता, इस युग के एक अग्रणी मार्क्सवादी चिन्तनकार एवं क्रान्तिकारी पार्टी–सोशिलिस्ट यूनिटी सैन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष की 40वीं बरसी पर उनके जीवन संघर्षों को याद करने और उनके विचारों व सीखों को जानने-समझने के लिए देश भर में स्मृति सभाएं आयोजित हुई। सभाओं में पहले कॉमरेड शिवदास घोष की फोटो पर सभा अध्यक्ष, मुख्य वक्ता, पार्टी व जनसंगठनों के नेताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया। स्मृति सभाओं की शुरूआत कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत से हुई और समापन अंतर्राष्ट्रीय गान से हुआ। सभाओं में जनवादी-क्रांतिकारी गीतों की भी प्रस्तुति हुई।

रोहतक (हरियाणा) : सर्वहारा के महान् नेता कॉमरेड शिवदास घोष की याद में एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट), हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से राज्य स्तरीय स्मृति सभा 7 अगस्त को छोटूराम पार्क, रोहतक में आयोजित की गई। अध्यक्षता कॉ. अनूपसिंह, सदस्य, हरियाणा राज्य कमेटी ने की। मुख्य वक्ता थे कॉमरेड शंकर साहा सदस्य, केन्द्रीय कमेटी, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) और महासचिव, एआईयूटीयूसी। सभा को कॉ. सत्यवान सदस्य, केन्द्रीय कमेटी एवं सचिव, हरियाणा राज्य कमेटी और कॉमरेड रामफल, राज्य कमेटी सदस्य ने भी सम्बोधित किया।

कॉ. सत्यवान ने अन्य बातों के अलावा कहा कि 2 साल पहले चुनावों में भाजपा ने 'अच्छे दिन' आने, विदेश से काला धन लाने, बेरोजगार युवाओं को 6000 व 9000 रु. भत्ता देने, बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को 2000 रु. मासिक पेन्शन देने, फसलों के 50 प्रतिशत लाभकारी दाम देने, बिजली 24 घन्टे देने, किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के अलावा सुशासन, सुरक्षा व सम्मान की गारन्टी जैसे वादे किये थे। परन्तु सत्ता

रोहतक : स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड शंकर साहा

में आते ही उन्हें ताक पर रख कर उल्ट-दिशा पकड़ ली। इन्हें चुनावी जुमले कहने में जरा सी भी लज्जा नहीं दिखाई। जनता में यह सरेआम धोखाधड़ी व राजनैतिक अपराध है। आज लोगों पर भारी टैक्स थोपे जा रहे हैं और पूंजीपति घरानों को अरबों-खरबों की छूट व कर्ज-माफी दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक धोखा कहा जो प्राइवेट कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं है। आरक्षण की आड़ में प्रदेश के लोगों के भाईचारे को बुरी तरह से तोड़ा गया है। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) प्रदेश भर में जनजागरण कर भाजपा सरकार की पोल खोलेगी। पार्टी ने 2 सितम्बर की आम हड़ताल को पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने भाजपा की वादा-खिलाफी और केन्द्र व प्रदेश सरकार की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

2 सितम्बर की देशव्यापी आम हड़ताल सफल करें

बीजेपी की ट्रेड यूनियन बीएमएस को छोड़ कर बाकी 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशनों की ओर से संयुक्त तौर पर 2 सितम्बर की देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया गया है। जनजीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण 12 सूत्री मांगों को लेकर मजदूर-कर्मचारियों की यह हड़ताल हो रही है। श्रम कानूनों में मजदूर-विरोधी संशोधनां को रद्द करने, सभी बेरोजगारों को नौकरी देने, न्यूनतम वेतन 18000 रुपये मासिक करने, महंगाई पर रोक लगाने के कारगर कदम उठाने, स्थायी प्रकृति के काम पर अस्थायी मजदूर नियुक्त न करने, सभी को पेन्शन देने, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील समेत सभी स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाने, असवेदन करने के 45 दिन के अन्दर यूनियन को पंजीकृत करने, इत्यादि मांगों पर यह हड़ताल होने जा रही है। इसके अलावा, बिजली, रोडवेज, पब्लिक हैल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम सरकारी विभागों, संस्थाओं व संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने की कुचेष्टा और बैंक, बीमा, रेलवे, रक्षा व अन्य सरकारी विभागों व खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दिये जाने के तीव्र विरोध में है यह हड़ताल।

कांग्रेस-नीत यूपीए के शासनकाल से ही घोर प्रतिक्रियावादी नई आर्थिक उदारीकरण की नीति का सफर शुरू हुआ, जिसकी निरंतरता बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी सरकार। कांग्रेस और बीजेपी, दोनों की ही सरकारों के शासनकाल में इन्हीं मांगों को लेकर कई बार सम्पूर्ण देशव्यापी हड़तालें हुई हैं लेकिन कांग्रेस की तरह ही बीजेपी सरकार भी पूंजीपति वर्ग के स्वार्थ में मजदूर-कर्मचारियों की उन सब जायज मांगों की न केवल अनदेखी कर रही है, बल्कि उससे भी तेज हमले कर रही है। इसी वजह से एक बार फिर हड़ताल का आह्वान करने को मजबूर हुए हैं मजदूर-कर्मचारी।

पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था बाजार संकट से ग्रस्त है। जो सालों साल से शोषण करते हुए धनकुबेर हो गये हैं, उन्होंने कहा है कि और अधिक मुनाफा चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि बाजार नहीं है। लोगों की खरीद शक्ति घट जाने से बाजार सिंकुड़ता जा रहा है। इसलिए शासकों का मूल मंत्र है पूंजीवाद के संकट का सारा बोझ मजदूरों के कंधों पर डाल दो। मजदूरी घटा दो। छंटनी कर दो। इसी को सुधार की संज्ञा दे दी है। अब तक जहां 100 मजदूर काम करते थे, ऐसे उद्योगों में छंटनी और तालाबंदी करने से पहले सरकार से मंजूरी लेना मालिकों के लिए लाजिमी था। अब कहा जा रहा है कि 300 से कम मजदूर जहां काम करते हैं ऐसे उद्योगों में छंटनी, तालाबंदी और ले-ऑफ के लिए सरकार से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। मालिक जब चाहे उनमें छंटनी, तालाबंदी, ले-ऑफ कर सकेंगे। श्रम कानूनों में इस संशोधन के चलते देश के 90 फीसद उद्योगपतियों को मजदूरों की छंटनी का बेरोकटोक अधिकार मिल जायेगा। बीजेपी सरकार 'अच्छे दिन' लाने के नाम पर 90 फीसद मेहनतकश लोगों के जीवन में इस तरह मौत का परवाना लिख देना चाह रही है। राजस्थान, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में उसने ऐसा कानून लागू भी कर दिया है।

आजादी मिले 70 साल हो गये हैं। अब तक भी केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई किसी भी सरकार ने सभी के लिए काम के अधिकार को संवैधानिक मान्यता नहीं दी है। लेकिन मालिकों को छंटनी करने, कारखाना बंद करने,

(शेष पृष्ठ 8 पर)

स्मृति दिवस 5 अगस्त

उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, देश ने याद किये महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष

(पृष्ठ 1 का शेष)

पूंजीपति-परस्त व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के आगामी 4 अक्तूबर 2016 को मुख्यमंत्री आवास पर करनाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन को सफल करने की अपील की।

स्मृति सभा में मुख्य वक्ता पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य एवं प्रसिद्ध श्रमिक नेता कॉमरेड शंकर साहा ने कहा कि यह स्मृति सभा हम ऐसे समय में कर रहे हैं जब दुनिया का बहुत बुरा हाल है। पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देशों में भीषण शोषण-दमन से लोग हाहाकार कर रहे हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहां गरीबी, भुखमरी, छंटनी, श्रमिक अधिकारों में कटौती के खिलाफ लड़ाई नहीं चल रही हो। लड़ाई हमारे देश में भी चल रही है। हमारे देश का मजदूर-किसान भी लड़ाई करने से, आन्दोलन करने से पीछे कभी नहीं रहा है। वह जान कुर्बान करने से कभी नहीं हिचकिचाया है। हमारे देश सहित दुनिया के मजदूरों ने बड़ी-बड़ी जुझारू लड़ाइयां भी लड़ी। बहुत कुर्बानियां भी दी। लेकिन इतनी लड़ाइयों और कुर्बानियों के बावजूद इन लड़ाइयों में कामयाबी क्यों नहीं मिली? लड़ाई का नेतृत्व सही नहीं हो तो लड़ाई में कामयाबी नहीं मिलती, उल्टे निराशा-हताशा छा जाती है। इसलिए सही नेतृत्व होना चाहिए। देश और दुनिया की मूल समस्याएं एक ही जैसी हैं। क्रान्ति के द्वारा ही ये समस्याएं हल हो सकती हैं। फिर सही क्रान्तिकारी पार्टी के बिना भी क्रान्ति नहीं हो सकती। हम अगर क्रान्ति करना चाहते हैं तो क्रान्तिकारी पार्टी को ताकतवर बनाना होगा। लेकिन हम लोग क्रान्तिकारी पार्टी को अभी इतना ताकतवर नहीं बना पाये हैं कि क्रान्ति कर सके। हां, हमने कोशिश की। हमें एसयूसीआई(सी) पार्टी को मजबूत करना होगा।

कॉमरेड साहा ने कहा कि हम लोग अगर खुद को नहीं बदल पाये तो समाज को भी नहीं बदल पायेंगे। हम खुद को नहीं बदलें और समाज बदल जाये, ऐसा होने वाला नहीं है। हमें पहले खुद को बदलना पड़ेगा फिर समाज बदलेगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने कोई मीटिंग बुलाई तो बस उसमें शामिल हो गये, कोई रैली हुई तो उसमें हाजिर हो गये। केवल इतने से काम नहीं चलेगा। आप सबको मिलजुल कर, एकजुट होकर क्रान्तिकारी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करनी है। सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन, उनकी शिक्षाओं को जानने, समझने और जीवन में लागू करने की भरसक कोशिश आपको करनी है। उनकी सीखों के आधार पर जन आन्दोलन को तेज करना है। लड़ाई को तेज करने की कोशिश अगर हम न करें तो फिर मीटिंगों में आने का कोई फायदा नहीं है। तब तो अपना समय नष्ट करने के सिवा और कुछ नहीं होगा। भाषणबाजी और नारेबाजी हो जायेगी। सुन कर घर वापस लौट जायेंगे। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। काम बनाने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। वरना हजारों हजार लोगों को क्रान्तिकारी आन्दोलन में ला नहीं पायेंगे। यह विज्ञान है। क्रान्ति तो आयेगी ही, समाज बदलता आया है और बदलता जायेगा, परिवर्तन होगा, बदलाव आयेगा। यह अटल नियम है। अगर हम नहीं तो कोई दूसरा क्रान्ति करेगा। वह भी तभी कर पायेगा जब कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन को अपना लेगा। कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा है कि राजनीति एक उच्च हृदयवृत्ति है, क्रान्तिकारी राजनीति तो और भी उच्च हृदयवृत्ति है। कॉमरेड शिवदास घोष ने यह भी कहा है कि चिंतन के क्षेत्र में हम बहुत आगे पहुंच गये हैं लेकिन हमारा जो हृदय है, दिल है वह छोटा रह गया है, वह अपने-अपने स्वार्थ की सोचता है, उसे सिर्फ अपने सुख-दुख की ही चिंता है, गांव-शहरों में रहने वाले दूसरे लोग किस हाल में जी रहे हैं, उनके बारे में कोई सरोकार नहीं रखता है। जबकि लाखों लाख लोगों को क्रान्ति के जंग-ए-मैदान में लाना पड़ेगा। वे तो आपको देखकर आयेंगे। आप उनसे भले ही कॉमरेड शिवदास घोष की कही हुई बातें बोलें, उससे क्या, वे तो यह देखेंगे कि आपकी जिन्दगी क्या है, कहीं कथनी और करनी में अंतर रहा तो वे आपको नहीं मानेंगे। वे देखेंगे कि आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। आप क्रान्ति के स्वार्थ के साथ अपना खुद का स्वार्थ मिलाने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। पार्टी हित के साथ अपना व्यक्तिगत हित एकाकार करने में लगे हुए हो या नहीं। जब तक ऐसा नहीं करोगे, तब तक कॉमरेड शिवदास घोष जिन्दाबाद बोलने से ही क्रान्ति आयेगी नहीं।

क्रान्ति का मतलब है आम जनता की रुचि-संस्कृति, नीति-नैतिकता, चिंतन-मनन, व्यक्तिगत सम्पत्ति व इससे जनित सोच, सब कुछ को बदल डालना होगा। क्रान्ति करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा बनाने की प्रक्रिया, तौर-तरीका आप अपना कर चल रहे हैं या नहीं। नेताओं सहित आप सब जो यहां बैठे हैं जरा विचार करके देखिये, क्या आप अपने साथ दस-बीस आदमियों को आन्दोलन में ला पाते हैं? नहीं ला पाते हैं तो इसलिए कि आप खुद नहीं बदले हैं। आप लोगों का विश्वास जीत नहीं पाये हैं। आप भरोसा करने लायक बन नहीं पाये हैं। आप आपने को क्रान्ति करने लायक तैयार नहीं कर पाये हैं। हमें उच्च संस्कृति चाहिए। मजदूर वर्ग की संस्कृति चाहिए। वह सर्वहारा संस्कृति आसमान से नहीं टपकती। वह तभी आ सकती है जब आप खुद को मजदूर आन्दोलन में झोंक दें, मजदूर वर्ग की लड़ाई में अपने को शामिल कर देते हैं, जेल जाते हैं, मार खाते हैं। आप किसी झंझट-झमेले में नहीं पड़ते, किसी को कोई हर्ज या नुकसान नहीं पहुंचाते ऐसे भले आदमी हैं, इसी से काम नहीं चलेगा। मजदूर वर्ग के आन्दोलन से ही मजदूर वर्ग की संस्कृति आयेगी। आप सब जानते हैं एक समय रूस में इन्कलाब आया था। महान लेनिन-स्टालिन के नेतृत्व में वहां क्रान्ति हुई थी। समाज का काया पलट हो गया था। देश का चेहरा ही बदल गया था। मजदूर-किसानों का जीवन बदल गया था। वहां भुखमरी, बेरोजगारी नहीं रही थी। शिक्षा-इलाज की कोई समस्या नहीं रही थी। सभी समस्याओं को उन्होंने दूर कर दिया था। वहां अन्दर से आधुनिक संशोधनवाद और बाहर से साम्राज्यवादी साजिश के चलते समाजवाद अब ढह चुका है। लेकिन फिर दोबारा लोग महान लेनिन-स्टालिन की तस्वीरें हाथों में लिये हुए जुलूस निकाल रहे हैं और पिछली गलतियों पर पछता रहे हैं। वे कहते हैं हमें मजदूर वर्ग का राज चाहिए।

हमारे देश की सत्ता में कायम पूंजीवादी व्यवस्था समाज पर कभी की एक भारी बोझ बनी हुई है। इसने लोगों को बेहद कंगाल बना दिया है। शंकर साहा ने जोर देकर कहा कि इस विकट स्थिति में कामरेड शिवदास घोष की विचारधारा एक रोशनी-पुंज का कार्य करती है और लोगों को उन्नत नीति-नैतिकता के आधार पर एकजुट कर जनमुक्ति व नई उन्नत सभ्यता की ओर अग्रसर करती है। केन्द्र की भाजपा सरकार की जनविरोधी, मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 सितम्बर को देशव्यापी हड़ताल होगी। इस आन्दोलन में हमारी ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी भी शामिल है। इसमें लाखों लाख लोगों, मजदूर-कर्मचारियों और छात्र-नौजवानों को शामिल कराना है। अभी हाल ही में फ्रांस में 30 लाख मजदूरों ने विशाल जुलूस निकाला जिसमें छात्र-नौजवान भी शामिल हुए।

साथियो, आप चाहे कितनी ही मीटिंगें करें, जुलूस में सड़कों पर अगर नहीं उतरे, लाखों लाख लोगों को जन आन्दोलन में सम्मिलित नहीं किया, सोते रहे या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो क्रान्ति नहीं होगी। ऐसे समाजवाद आने वाला नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता। आपको निराश करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। समाजवाद तो आयेगा ही। यह विज्ञान कहता है। लेकिन सोते रहे तो हम नहीं ला पायेंगे। यह निर्भर करता है हम लोगों की पहलकदमी पर, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की पहलकदमी पर। अगर हम पहलकदमी ही नहीं कर पाये तो भला हम कैसे समाजवाद ला पायेंगे। समाजवाद अपने आप भी नहीं आयेगा। हमें पीछे छोड़कर कोई और आगे बढ़ जायेगा। हम नहीं तो कोई दूसरा पहलकदमी कर इसे लायेगा। आप यह पहलकदमी जरूर करेंगे इस उम्मीद और भरोसे के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

दिल्ली : एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) की दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी द्वारा सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर 5 अगस्त को गाँधी शांति प्रतिष्ठान सभागार में एक जनसभा आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी सचिव कॉ. प्राण शर्मा ने की। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य एवं ए.आई.यू.टी.यू.सी. के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा थे। सभा में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों व तबकों से आए सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया

सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड शंकर साहा ने कहा कि झौंपड़ी छोड़ कर राजमहल में आने को जिस तरह त्याग नहीं कहते उसी तरह एक क्रान्तिकारी भी पुरानी घटिया जिन्दगी को छोड़कर एक उन्नत दर्जे की जिन्दगी पाता है। इसे वह कोई त्याग नहीं समझता है। उन्होंने कॉमरेड शिवदास घोष की यह सीख याद दिलाई, ''एक सही क्रान्तिकारी ने कुछ भी 'त्याग' नहीं किया है, बल्कि घर-बार, रुपया-पैसा, धन-दौलत और ऐशो-आराम आदि वह जो कुछ छोड़ कर आया है उसकी तुलना में लाखों करोड़ों गुना अधिक बड़ी चीज वह पा गया है। उसने अपनी सही इज्जत और मान-मर्यादा की भावना को वापस पा लिया है।''

(शेष पृष्ठ 4 पर)

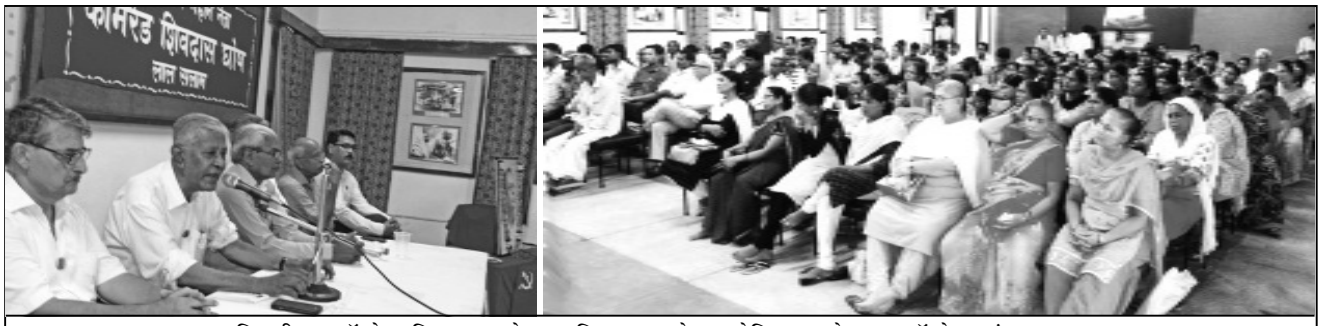

दिल्ली : कॉमरेड शिवदास घोष स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड शंकर साहा

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)

कर निर्धारण व बेहतर कर वसूली के पीछे इजारेदारों की जरूरत के मद्देनजर आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के लिए उठाया गया कदम

पिछले कई वर्षों से भारत सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू करने की बात कर रही है। अब यह संसद में पास हो गया है। हमारे देश में वर्तमान में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर मसलन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वैट, चुंगी, प्रवेश कर, सीमा शुल्क, लक्जरी टैक्स, प्रतिकारी शुल्क, सेवा कर इत्यादि मौजूद हैं। जी.एस.टी. इन सभी करों को एक में समाहित करता है। सेवा सामान और सेवाओं पर एक कर वसूले जाएंगे, वह है जी.एस.टी.। सन् 2009 में कांग्रेस सरकार ने इसे सबसे पहले चर्चा के लिए प्रस्तावित किया तथा अब बीजेपी सरकार इसे क्रियान्वयन के लिए अभिलेखित कर रही है। आज की तिथि में सी.पी.आई.(एम) सहित लगभग सभी विपक्षी दल इस बिल दर को 18% तक सीमित करने की बात बोल रहे हैं। वे ऐसा सिद्धांत के मद्देनजर नहीं कर रहे हैं बल्कि वे इसे बीजेपी सरकार से सौदा करने का औजार बना रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उन सभी को जी.एस.टी. को बखूबी समझने की कोई चिन्ता नहीं है कि यह जनता को और दरिद्र बनाएगा एवं उसकी कमर तोड़ेगा या नहीं। वास्तव में उनका जनता के समक्ष कुछ इस प्रकार भाव भंगिमा है मानो जी.एस.टी. सरकार की तरफ से एक सराहनीय कदम है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत विवाद विपक्षी दलों की ओर से खड़ा किया गया, वह जी.एस.टी. के कुल संग्रह में से राज्यों के हिस्से के वितरण के संदर्भ में था, जो अधिकतर विपक्षी दल या कांग्रेस द्वारा संचालित है। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली का यह आश्वासन है कि जी.एस.टी. की वजह से राज्यों के राजस्व में किसी भी प्रकार की कमी की भरपाई कर दी जाएगी, हल्के फुल्के विरोध के स्वर भी बन्द हो गए। ऐसे माहौल में शासक इजारेदार की इच्छा तथा उनके फायदे के लिए विपक्षी दलों के बिना किसी विरोध के यह योजना को लागू कर दी गई। वित्त मंत्री का दावा है कि जी.एस.टी. का आगमन भारत को एक बाजार में बदल देगा, टैक्स पर टैक्स को रोकेगा, वस्तु एवं सेवा सस्ती होगी तथा यह व्यापार को आगे बढ़ाएगा। जी.एस.टी. की वकालात करने वालों ने यह भी दावा किया है कि यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में 2% प्रति वर्ष वृद्धि करेगा। आइये हम इन तमाम दावों की विश्वसनीयता की जाँच की ओर अग्रसर होते हैं तथा फिर देखते हैं कि जी.एस.टी. को लागू करने के पीछे नीयत क्या है?

जनहित में नहीं हो सकता पूँजीवाद में सुधार का कोई भी कदम

जी.एस.टी. के ऊपर ऐसे किसी चर्चा में जाने के पहले यह दोहरा देने की जरूरत है कि ऐसा कोई उपाय या कदम या सुधार नहीं हो सकता जिसे एक पूँजीवादी देश में बुर्जुआ सरकार दिखावे के तौर पर लाती है या पहल करती है वह शासक इजारेदारों के हित में न हो। हाल के दिनों में जब भूमण्डलीकरण, उदारीकरण के अभिलेख पर आधारित तमाम पूँजीवादी-साम्राज्यवादी दुनिया बढ़ती हुई तीव्र अनसुलझी आर्थिक संकट के निदान के लिए बेचैनी से कोशिश में लगी है अलबत्ता सब व्यर्थ, एक या सभी पूँजीवादी देशों के पूँजीवादी शासक, उनके राजनैतिक प्रबंधक तथा केयरटेकर सरकार देशी तथा विदेशी दोनों इजारेदारों तथा कॉर्पोरेटों के साधारणतया हित साधने के उद्देश्य से कानून बनाते हैं, अधिनियम लादते हैं तथा प्रक्रियाओं का पैबंद लगाते हैं। जनमानस को धोखा देने के लिए, अपनी कारगुजारियों पर पर्दा डालने के लिए ढेर सारे झूठे वायदे तथा आश्वासनों का मुलम्मा चढ़ा देते हैं। इसलिए यह भ्रामक व स्वयं को धोखा देना होगा अगर कोई इन कदमों, नियमों, अधिनियमों, सुधार आदि से किसी भी प्रकार की राहत की उम्मीद बना बैठे हों। हर गुजरते दिन के साथ तीव्र होते आर्थिक संकट के साथ-साथ पूँजीवादी इजारेदार शासक भी आर्थिक तथा राजनैतिक शक्ति दोनों को अपने हाथों में केन्द्रीकृत तथा समाहित कर लेने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी भी प्रकार के विरोधी स्वर का दमन कर सके। बहुत चालाकी से वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटका सके व मीठे-मीठे वचनों की आड़ में अपने कृत्यों को छुपा सके। हम लोगों को इस समझदारी के साथ जी.एस.टी. पर चर्चा करनी चाहिए। यह समझ लेने की जरूरत है कि जी.एस.टी. का प्रारूप भी विनाशकारी, मरणासन्न पूँजीवाद, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण की नीतियों का एक हिस्सा मात्र है जिसे भारत सरकार ने पाला पोसा है तथा लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कर प्रणाली कितनी सरल तथा परेशानी मुक्त हो जाएगी बल्कि समझना यह है कि किस प्रकार एकीकृत कर प्रणाली की केन्द्रीकृत तथा समावेशी शक्ति जनता का अधिकतम खून निचोड़ेगी।

जी.एस.टी. – विस्तार से व्याख्या

जी.एस.टी. के पक्षधर यह तर्क देते हैं कि बहु कर प्रणाली कर चोरी से लेकर गलत गणना तथा विवाद विभिन्न प्रकार की समस्या पैदा करता है। इससे इतर ज्यादा से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के माध्यम से, ज्वाइंट वेन्चर में, कूटनीतिक गठबंधन आदि के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, इस कारण कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना समय की मांग है। इसके अतिरिक्त बहुकर स्थिति में दुहरा कर या टैक्स पर टैक्स का प्रपाती प्रभाव कायम है। जी.एस.टी. इन सभी समस्याओं का हल है। वितरण कड़ी में केवल अंतिम उपभोक्ता को ही पिछले सभी चरणों के बेनिफिट के साथ आखिरी विक्रेता द्वारा चार्ज किया गया जी.एस.टी. भरना पड़ेगा (मतलब वितरण कड़ी के बाद के चरणों में टैक्स पूर्व में दिया टैक्स घटाकर देय होगा) प्रसंगवश वितरण कड़ी मूल्य प्रतिपादन प्रक्रिया का तकनीकी नामकरण है। इसमें कच्चे माल के इंतजाम से लेकर तैयार माल को खुदरा दुकान में बिक्री है जो अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम भागीदार से बना है तथा वह कम्पनी एवं ग्राहक के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है। बहरहाल अपस्ट्रीम कम्पनी का वह समूह है जो सामान या सेवा के लिए कच्चा माल, अवयव, घटक, सूचना, पूँजी तथा विशेषज्ञ आपूर्ति करता है। जबकि डाउनस्ट्रीम में विक्रयवाहक सम्मिलित हैं जैसे थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता। अर्थशास्त्र की भाषा में वितरण कड़ी के हर स्तर में वहाँ मूल्य का योग होता है। जब कच्चा लेदर को शोधित लेदर शीट में ढाला जाता है तब एक इकाई मूल्य का योग बनता है। जब इन शोधित शीट को लेदर बैग विनिर्माण के लिए भिन्न आकारों में काटा जाता है तो यह मूल्य योग का दूसरा स्तर होता है। फिर जब इन विशेष आकार के कटे टुकड़े को बैग बनाने के लिए सीला जाता है तो यह अगला मूल्य योग का चरण होता है तथा इसी तरह। उदाहरण के लिए वर्तमान में अगर एक मिनरल बोतल का फैक्ट्री मूल्य यदि 100 रुपये है तथा उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर प्रत्येक 10 रुपये है तो बोतल की कीमत बढ़कर 120 रुपये होती है। इस 120 पर राज्य सरकार 10% वैट उगाहती है। बोतल का अंतिम मूल्य 132 रुपये हो जाता है (100+20+12=132)। ऐसा क्यों? क्योंकि A विक्रय कर जोड़कर B को सामान बेचता है तथा B विक्रय कर जोड़ कर C को सामान बेचता है। चूँकि B अपने विक्रय कर दायित्व का हिसाब लगाता है वह भी विक्रय कर जो पहली खरीददारी में ही भुगतान हो चुका है, जोड़ देता है। इस प्रकार टैक्स पर टैक्स बन जाता है। उनके लिये जो 'प्रपाती प्रभाव' प्रक्रिया को थोड़ी और गहराई से देखना चाहते हैं हमलोग लेदर से लेदर बैग बनाने तथा फिर इसे बाजार में बेचने का एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि एक इकाई लेदर बैग के साथ एक इकाई श्रम एक इकाई लेदर बैग निर्मित करता है। मान लेते हैं कि पारिश्रमिक दर 100 रुपये है। एक इकाई लेदर बैग का करमुक्त मूल्य 100 रुपये है। लेदर बैग विनिर्माण में मुनाफे का मार्जिन 20% है तथा उत्पादित लेदर तथा लेदर बैग प्रत्येक पर 10% अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तब एक लेदर बैग 277.20 रुपये में बेचा जाएगा (100 रुपये का लेदर 10% टैक्स 100 रुपये का पारिश्रमिक) (1+20% मुनाफे का मार्जिन) (1+10% टैक्स) कुल टैक्स की राशि 35.20 रुपये होगी जिसमें 10 रुपये लेदर का तथा 25.20 रुपये लेदर बैग का होगा। लेदर बैग पर 25.20 रुपये का टैक्स में 1.20 रुपये का टैक्स पूर्व में दिये गये टैक्स का टैक्स है। पूर्व में दिये गये टैक्स ने कीमत बढ़ा दी। इसलिए लेदर बैग का अन्तिम मूल्य ([10 रुपये लेदर पर भुगतान किया टैक्स + इस पर 20% का मुनाफे का मार्जिन जिसने 10 रुपये कीमत को बढ़ा दिया]10% टैक्स से गुणक)। इसलिए जाहिर है कि पहले से दिया हुआ टैक्स ज्यादा टैक्स के भुगतान का कारण बनता हे। यह है तथाकथित 'अनैतिकता'। क्योंकि टैक्स क्रिया के स्तर पर वसूली जाती है मतलब वितरण कड़ी के किस स्तर पर कितना मूल्य का योग हुआ है। यह तर्क दिया गया है कि जी.एस.टी. इस अनैतिकता को समाप्त कर देगा। वर्तमान में सभी टैक्स जबकि उत्पादन स्तर पर लगाए जाते हैं जी.एस.टी. इष्ट सिद्धांत सम्बद्ध उपभोग आधारित होगा। उत्पादन केन्द्र से सामान बाहर निकालने के साथ उत्पादन शुल्क या सामान की आपूर्ति होने पर वैट (VAT) के प्रचलित व्यवहार के विपरीत जी.एस.टी. वस्तु एवं सेवाकर जहाँ अन्तिम उपभोग संघटित होगा उसी जगह लागू होगा। दूसरे शब्दों में जी.एस.टी. वहन करने का दायित्व आपूर्ति के समय खड़ा होगा। यह वितरण कड़ी में मूल्य योग वस्तु एवं सेवा की प्रत्येक स्तर पर बिकवाली व खरीददारी पर संग्रह किया जाएगा। जी.एस.टी. वस्तु एवं सेवा के इंतजाम के मुकाबले इसकी आपूर्ति पर भुगतान होगा। उत्पादक या थोक व खुदरा विक्रेता लागू जी.एस.टी. दर वहन करेंगे किन्तु टैक्स क्रेडिट प्रक्रिया के द्वारा इसे वापसी का दावा करेंगे। चूँकि जी.एस.टी. आपूर्ति आधारित होगा, यह तीन प्रकार के होंगे - CGST (केन्द्रीय जी.एस.टी.), SGST (राज्य जी.एस.टी.) तथा IGST (अंतर्राष्ट्रीय जी.एस.टी.)। अगर सामान लखनऊ से इलाहाबाद जाता है (मानो राज्य के अन्दर) तो केन्द्रीय जी.एस.टी. और राज्य जी.एस.टी. दोनों वहन करने होंगे। संग्रहित राशि केन्द्र व राज्य सरकार को अनुपातिक रूप में जाएगी। अगर सामान को इलाहाबाद से आगरा पुनः बेचा जाता है तब फिर राज्य के अन्दर बिक्री के ऊपर केन्द्रीय जी.एस.टी. तथा राज्य जी.एस.टी. दोनों लगेंगे। विक्रय मूल्य में वृद्धि होगी तथा इस तरह टैक्स दायित्व भी बढ़ेगा। अगर सामान अमृतसर जाता है (अन्तर्राज्यीय) तथा बेचा जाता है तब केवल IGST लगेगा तथा यह सम्पूर्ण केन्द्र सरकार को मिलेगा। स्पष्टतः वह अन्तिम उपभोक्ता होगा जिसे अन्तिम मूल्य या खुदरा मूल्य पर सम्मिश्रित जी.एस.टी. चढ़ाकर तमाम टैक्स राशि वसूली जाएगी। अन्तिम मूल्य सामान की आवाजाही के साथ आपूर्ति बिन्दु पर निर्भर करेगा तथा इसी आधार पर इसके दाम बढ़ेंगे। जी.एस.टी.के समर्थक कहते हैं कि बहुटैक्स का सरलीकृत स्वरूप जी.एस.टी. द्वारा प्रणाली में दोहरे भार के खात्मे में ग्राहक को अन्तिम मूल्य कम देना होगा। वे दावे के साथ कहते हैं कि वर्तमान टैक्स व्यवस्था में उपभोक्ता को विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क (सबसे ज्यादा लगभग 12.5%) तथा वैट के कारण क्रय मूल्यों से 25% से 26% अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। यद्यपि अब तब जी.एस.टी. दर के बारे में किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं है। बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों तथा रणनीतिकारों का मत है कि यह 18% से 22% के बीच रहेगा। इसी अनुमान के आधार पर उनका दावा है कि इससे वस्तु व सेवा आनुपातिक सस्ते हो जाएंगे। किन्तु जी.एस.टी. एक्ट में अविश्वसनीय शर्तें मौजूद है। जैसा जी.एस.टी. के बारे में कहा गया है कि यह टैक्स पर टैक्स को समाप्त करता है हम पहले दिखा चुके हैं कि क्योंकि खरीददार समायोजित टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit-ITC) पर क्लेम करने को अधिकृत है जिसे विक्रेता ने वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए खरीददारी के समय भुगतान किया था। किन्तु एक्ट कहता है कि विक्रेता जी.एस.टी. भुगतान किया है या नहीं यह जाँचने का भार खरीददार का होगा। पहले से ही इस तरह के दुष्कर प्रावधान के अव्यवहारिक होने की शिकायत हो रही है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है अगर समायोजित टैक्स क्रेडिट सम्भव नहीं होता है तब कैसे प्रपाति प्रभाव को रोका जाएगा। तथा अगर टैक्स पर टैक्स कायम रहता है तब फिर परिष्कृत कर प्रणाली वर्तमान कर प्रणाली से बेहतर कैसे होगी। इन तमाम सन्दर्भित प्रश्नों का जवाब जानने के लिए ये बारीकी से देखना पड़ेगा कि जीएसटी की नीति में क्या कुछ अनूठा है?

जी.एस.टी. के पीछे सिद्धांत में क्या कुछ है अनूठा?

आइये हम लोग 1 अप्रैल 2005 में चलते हैं जब वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लाया गया था। उससे पहले टैक्स नीतियों के रणनीतिकार यह तर्क देते थे कि प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, नगरपालिका कर, सम्पत्ति कर आदि द्वारा उगाही किया राजस्व विकास के लिए जरूरी राशि से कम रह जाता है। इसलिए वे जिनकी आय निम्न होने के कारण प्रत्यक्ष कर देने के लिए काफी गरीब हैं वे भी टैक्स भरने के लिए बाध्य होते हैं। तभी से प्रत्यक्ष कर प्रणाली आयी जिसे सर्वसाधारण जनता वस्तु एवं सेवा के अंतिम बाजार मूल्य के घटक के रूप में वहन करती है। बुर्जुआ सरकार तब जो तथ्य छुपा ली तथा अब भी छुपा रही है कि राजकोषीय घाटा प्रत्यक्ष करों से वसूली गई अपर्याप्त राजस्व के वजह से नहीं है यह इस बात से है कि बड़े औद्योगिक घराने, एकाधिकार उद्योगपति तथा मुट्ठी भर अत्यधिक अमीर व्यापक पैमाने पर कर चोरी तथा कर बकाया रखते हैं। वे नियमों को बदलकर दण्डमुक्त हो जाते हैं तथा खजाने की लूट करते है। वे अपने वास्तविक आय को चालाकी से छुपाते हैं तथा आर्थिक तंत्र को बर्बाद करने के लिए काफी मात्रा में काला धन बनाते हैं। इससे

(शेष पृष्ठ 7 पर)

स्मृति दिवस 5 अगस्त

मरणासन्न पूंजीवाद के अंधेरे में है आशा की एक किरण की तरह

पटना : स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान

(पृष्ठ 2 का शेष)

पटना, (बिहार) : इस युग के अग्रणी मार्क्सवादी चिंतक, सर्वहारा के महान नेता, शिक्षक, पथ प्रदर्शक व हमारी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष की स्मृति सभा पटना में 5 अगस्त को स्थानीय आईएमए हॉल में आयोजित हुई। सभा के पूर्व सुबह में राज्य कार्यालय में पार्टी का झंडा राज्य सचिव कॉमरेड शिव शंकर ने फहराया। तत्पश्चात् कॉमरेड शिवदास घोष की तस्वीर पर माल्यार्पण हुआ।

आईएमए हॉल में सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की तस्वीर पर पार्टी के केन्द्रीय कमिटी सदस्य, हरियाणा राज्य सचिव तथा स्मृति सभा के मुख्य वक्ता कॉमरेड सत्यवान; बिहार राज्य सचिवमंडल सदस्य तथा स्मृति सभा के अध्यक्ष कॉमरेड अरूण कुमार सिंह, मंच पर उपस्थित एआईडीवाईओ की महासचिव कॉमरेड प्रतिभा नायक तथा राज्य कमिटी के अन्य सदस्यों ने माल्यार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि विश्व पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था के अभिन्न अंग होने की वजह से अपने देश की जनसंख्या का 90 फीसदी गरीब, शोषित-पीड़ित आम-अवाम घोर आर्थिक संकट की गिरफ्त में है। 'अच्छे दिन' लाने का तिलिस्म अब टूट चुका है। बेलगाम महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी जंगल की आग की तरह फैल रही है। उद्योग एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। लाखों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में दम तोड़ रही पूंजीवादी व्यवस्था के तहत आजादी के 69 सालों का प्रत्यक्ष अनुभव दर्शाता है कि अडानी-अंबानी, टाटा-बिड़ला का विकास तथा गरीबों-सामान्य जनों का विकास एक साथ संभव ही नहीं है। यही वजह है कि एक ओर कुछ मुट्ठीभर अमीर और अमीर, तो दूसरी ओर बहुसंख्य गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। जन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को छीना जा रहा है। उन्होंने कॉमरेड घोष के कथन को याद दिलाते हुए कहा कि जैसे-जैसे पूंजीवाद का संकट तीव्र होता जाता है और पूंजीवादी राजसत्ता के खिलाफ मेहनतकश आवाम का संघर्ष तेज होता जाता है, वैसे-वैसे वह अधिकाधिक फासिस्ट रुख अख्तियार करता जाता रहा है। साथ ही पूंजीवाद-विरोधी संघर्षों को गुमराह करने के इरादे से धार्मिक, जातीय एवं नस्लवादी जज्बातों को उकसाने की कोशिश करता है। उन्होंने आगे कहा कि समस्याओं के खिलाफ जनता संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ रही है। वह इन तमाम समस्याओं के जनक शोषण पर आधारित पूंजीवादी निजाम का खात्मा चाहती है। देश में क्रांति की वास्तविक स्थिति मौजूद है। लेकिन क्रांतिकारी पार्टी क्रांति के लिए पूर्णरूपेण तैयार नहीं है। इसके लिए जरूरी है कॉ. शिवदास घोष के विचारों को जीवन में उतारते हुए उच्च सैद्धांतिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्तर हासिल करना ही सर्वहारा के इस महान नेता के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजली होगी।

सभा की अध्यक्षता करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड अरूण कुमार सिंह ने कहा कि राज्य की नीतीश-लालू सरकार भाजपा नेतृत्ववाली केन्द्र सरकार के जनविरोधी कदमों व नीतियों के खिलाफ ताल तो ठोंक रही है, लेकिन व्यवहार में पूंजीपतियों-उद्योगपतियों के हित में बनी भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण व ठेकाकरण की नीतियों को ही अपने यहां लागू करते हुए गरीब-गूरबों की तकलीफ की घड़ियां बढ़ा रही हैं। आज जब इन खतरनाक हमलों के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करना अत्यंत आवश्यक है, ऐसे में कोई भी दल, यहां तक कि वामपंथी पार्टियां भी नारेबाजी के अलावा कोई वास्तविक प्रतिरोधात्मक आंदोलन विकसित नहीं कर रही हैं।

लखनऊ (उ.प्र.) : 7 अगस्त को अमीनाबाद, लखनऊ स्थित गंगाप्रसाद वर्मा मेमोरियल हाल में महान मार्क्सवादी चिन्तक, सर्वहारा के महान नेता शिक्षक व पथ-प्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष की 40वीं स्मृति सभा सम्पन्न हुई। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड गोपाल कुण्डू ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज देश में जो संकट दिखाई पड़ रहा है, उसका मुख्य कारण संकटग्रस्त पूँजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूरी पूँजीवादी-साम्राज्यवादी दुनिया मन्दी से ग्रस्त है, उद्योग-धन्धों, कल-कारखानों का विकास नहीं हो रहा है। इसी कारण जन-जीवन संकट ग्रस्त होता जा रहा है। कॉ. कुण्डू ने यह भी कहा कि कॉमरेड शिवदास घोष का चिन्तन आज दिशा दिखा रहा है। हमारी पार्टी कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों के आधार पर समाज को सचेत व संगठित करते हुए व्यवस्था को बदल देगी। तभी समाज संकट से मुक्त होगा। कॉ. कुण्डू ने कॉमरेड शिवदास घोष के जीवन-संघर्ष की तमाम घटनाओं को आदर्श उदाहरण की तरह पेश करते हुए सच्चे कम्युनिस्ट व कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण व विकास की पद्धति का वर्णन किया। इनके अतिरिक्त राज्य सचिव मण्डल के सदस्य कॉ. विजय पाल सिंह ने भी अपना वक्तव्य रखा। अध्यक्षीय भाषण पार्टी राज्य सचिव कॉ. वी.एन. सिंह ने दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सभी उपस्थित कार्यकर्ता समाज में कॉमरेड शिवदास घोष के चिन्तन को प्रसारित व प्रचारित करें। सभा की शुरुआत कॉमरेड शिवदास घोष के चित्र पर माल्यार्पण व उन पर रचित गान से हुई और समापन अन्तर्राष्ट्रीय गीत से हुआ। राज्य सचिव मण्डल के सदस्यों कॉ सपन

लखनऊ : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड गोपाल कुण्डू (इनसैट में)

मुम्बई : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड द्वारकानाथ रथ

चटर्जी, पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा व रविशंकर मौर्य आदि ने भी माल्यार्पण किया।

मुम्बई (महाराष्ट्र) : एसयूसीआई (सी) की मुम्बई सांगठनिक कमेटी के द्वारा पार्टी के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर जनता केन्द्र तुलसीवाड़ा तारडियो सेण्ट्रल मुम्बई पश्चिम में एक जनसभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता पार्टी की मुम्बई सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. अनिल कुमार त्यागी ने की। मुख्य वक्ता थे कॉमरेड द्वारकानाथ रथ, सचिव, गुजरात राज्य सांगठनिक कमेटी, एसयूसीआई (सी)। सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. द्वारकानाथ रथ ने बीजेपी-आरएसएस की मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ साम्प्रदायिक राजनीति और दलितों के खिलाफ जातिवादी राजनीति की कड़ी निन्दा की। उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवादी और गांधीवादी लोग सम्प्रदायवाद और जातिवाद की खिलाफत अपने-अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐतिहासिक रूप से साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति के युग में अपनी मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुके पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत ही। पूंजीवाद अब प्रगतिशील नहीं रहा है, बल्कि प्रतिक्रियावादी और मरणासन्न हो चुका है। समाज में विभिन्न तबकों की एकता से अब पूंजीवाद डरता है। इसलिए इस व्यवस्था में पूंजीवादी पार्टियां फूटपरस्ती की राजनीति, जैसे सामप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद को प्रश्रय दे रही हैं। इस फूटपरस्त राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें लोगों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एकताबद्ध करना होगा और पूंजीवाद- विरोधी समाजवादी क्रान्ति को साकार करने के लिए इसके परिपूरक जन आन्दोलन गठित करना होगा। उन्होंने विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करने के भी कारणों पर प्रकाश डाला और 1960 से पहले संयुक्त महाराष्ट्र की मांग को लेकर किये गये आन्दोलनों और विभिन्न पार्टियों की उसमें भूमिका के बारे में भी विस्तार से बताया। सभा का समापन अन्तर्राष्ट्रीय गान से हुआ।

नागपुर (महाराष्ट्र) : इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतक सर्वहारा के महान नेता तथा एसयूसीआई(सी) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर यहां पंध्राबोदी रामनगर के जिला कार्यालय में एक स्मृति सभा की गई। इसकी अध्यक्षता पार्टी की नागपुर सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. विजयेन्द्र राजपूत ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) की उड़ीसा राज्य कमेटी के सचिव कॉ. धुर्जटी दास ने अपने भाषण में बताया कि किस तरह का संघर्ष करके कॉमरेड शिवदास घोष ने भारत की एक सही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया ताकि जनता की विभिन्न समस्याओं को हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सांस्कृतिक गिरावट अपने चरम पर है। कॉमरेड शिवदास घोष ने बताया है कि जब तक कोई निजी सम्पत्ति ही नहीं बल्कि निजी सम्पत्ति जनित मानसिकता के खिलाफ भी कठिन संघर्ष न करे तब तक वह सही मायने में कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना निहायत जरूरी है। उसी से हम विभिन्न समस्याओं से मानवजाति

(शेष पृष्ठ 6 पर)

एआईडीएसओ का धरना

भुवनेश्वर : एआईडीएसओ की उड़ीसा राज्य कमेटी द्वारा विभिन्न शिक्षा समस्याओं के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। छात्रों की एक सुसज्जित रैली भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई और लोअर पीएमजी पर जाकर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के पश्चात उच्च शिक्षा मंत्री/स्कूल शिक्षा मंत्री और जन शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।

एआईडीएसओ ने सरकार से मांग की कि प्लस टू की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएं। राज्य के सभी कॉलेजों में आर्ट, साइंस और कामर्स स्ट्रीम शुरू की जाए, सभी स्तरों पर फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाए, पास-फेल सिस्टम को कक्षा पहली से लागू किया जाए और ग्रेड प्रणाली, सेमेस्टर सिस्टम, च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम को खत्म किया जाए। एआईडीएसओ ने एमसीआई के नियमों को भरने, मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बढ़ाने तथा नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी मांग की। उन्होनें छात्र-विरोधी, शिक्षा-विरोधी नई शिक्षा नीति 2016 को रद्द करने की मांग की।

एआईडीवाईओ ने समस्याओं के समाधन की मांग पर किया प्रदर्शन

दिल्ली : 9 अगस्त को एआईडीवाईओ की शकूर पुर यूनिट द्वारा साफ-सफाई, मच्छरों को मारने की दवा तथा डेंगू के प्रकोप को रोकने के इंतजाम के लिए स्थानीय विधायक के कार्यालय प्रदर्शन किया गया। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जितेन्द्र सिंह तोमर को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व एआईडीवाईओ की राज्य सचिव प्रकाश देवी ने किया। गुड्डू, गौतम, आफताब, कशफी, दीपक आदि प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे।

विधायक ने 15 दिनों में डेंगू की रोकथाम के लिए दवाई छिड़कवाने, नालियों में दवा डलवाने तथा साफ-सफाई को सुचारू करने का वादा किया।

प्रेमचन्द की 136वीं जयंती कार्यक्रम

दिल्ली : 31 जुलाई 2016 को महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचन्द की 136वीं जयंती पर एआईडीएसओ की गुलाबी बाग-किशनगंज इकाई ने किशनगंज स्थित समुदाय भवन में चित्रकला, गीत, नृत्य, क्विज़ व भाषण प्रतियोगिता आयोजित की। सभा को मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के दिल्ली राज्य अध्यक्ष प्रो. नरेन्द्र शर्मा, एसयूसीआई(सी की स्थानीय सचिव व एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य सचिव कॉ. रितु कौशिक एवं ए.आई.डी.एस.ओ. के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रशान्त कुमार ने भी संबोधित किया।

प्रो. नरेन्द्र शर्मा के साथ ही, एस.यू.सी.आई.(सी) के राज्य कमेटी सदस्य कॉ. रमेश पाराशर, कॉ. रितु कौशिक, कॉ. प्रशान्त कुमार, ए.आई.एम.एस.एस. की स्थानीय सचिव कॉ. आशा रानी, ए.आई.डी.एस.ओ. के स्थानीय अध्यक्ष कॉ. श्रीराम सहनी, स्थानीय सचिव कॉ. सुनीधि, ए.आई.डी.एस.ओ. के स्थानीय इकाई सदस्य कॉमरेड्स पुनीत, चन्दन, जान्हवी, ए.आई.एम.एस.एस. की सदस्य कंचन व बबिता, ए.आई.डी.वाई.ओ. के सदस्य सिद्धार्थ व मंजीत ने विजित छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए।

सभा को सम्बोधित करते हुए प्रो. नरेन्द्र शर्मा

शहीद खुदीराम बोस स्मृति सभा

दुर्ग (छ.ग.) : 11 अगस्त को ए.आई.डी.एस.ओ. के द्वारा साईन्स कॉलेज दुर्ग में कई कक्षाओं में शहीद खुदीराम बोस शहादत दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया गया व सभा की गई।

सर्वप्रथम कॉलेज के प्राफेसरों व छात्र-छात्राओं ने उनकी फोटो पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजली अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि इन क्रांतिकारियों ने देश में ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें तमाम तरह के शोषण-उत्पीड़न समाप्त हों, सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क व समान शिक्षा का अधिकार हो, गरीबी व बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। किन्तु ऐसा न होकर तमाम समस्याए विकराल रूप में बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम विद्यार्थियों को संघर्ष करने की जरूरत है।

इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र-छात्राएं शामिल हुए व भाषण प्रतियोगिता करवा कर पुरस्कार वितरण किया गया।

नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाया

दुर्ग (छ.ग.) : मेडिकल सर्विस सेन्टर (एम.एस.सी.) एवं अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन (ए.आई.एम.एस.एस.) के द्वारा 31 जुलाई को शहीद भगत सिंह स्कूल के पास, तितुरडीह दुर्ग में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया और मरीजों को दवाई वितरण किया। इस अवसर पर डॉ. प्राची अरोरा (जनरल फिजीशियन), डॉ. सतीश चन्द्राकर, डॉ. देव ज्योति, डॉ. स्निग्धा उपाध्याय (दंत रोग विशेषज्ञ) सहित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. करूणा कश्यप, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. रितेश वाल्मिकी का नि:शुल्क चिकित्सा शिविर विशेष सहयोग रहा। इस शिविर में 210 मरीजों का इलाज किया गया जिसमें दाँत की समस्या, मौसमी बीमारियों, महिलाओं में कमजोरी, खून की कमी, हाथ पैरो में झुनझुनी, साथ ही बच्चों में कृमि, सर्दी, खासी, बुखार से ग्रस्त मरीज मिले। मरीजों में ज्यादातर पेट की बीमारी जैसे पेट दर्द की शिकायत, गैस्ट्राइटिस के मरीज मिले। इस अवसर पर मेडिकल सर्विस सेन्टर दुर्ग की जिला इंचार्ज नर्स अनिता साहू, पैरामेडिकल स्टाफ आत्मा राम साहू, मोहनीश राजपूत, आदि उपस्थित थे।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद को याद किया

दुर्ग (छ.ग.) : 23 जुलाई को ऑल इण्डिया डीवाईओ के द्वारा जिला दुर्ग, रायपुर और कांकेर जिले के पंखाजूर शहर में आजादी आन्दोलन की गैर-समझौतावादी धारा के महान क्रान्तिकारी योद्धा शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जयंती पूरे सम्मान के साथ मनायी गई। कार्यकर्ताओं, आम छात्र-नौजवानों से अपील की गई कि हर तरह के सामाजिक अन्याय, शोषण, बेरोजगारी, अपसंस्कृति, नशाखोरी के खिलाफ जोरदार आन्दोलन निर्मित करने के लिए आगे आयें। ऑल इण्डिया डीएसओ के द्वारा दुर्ग जिले में साइन्स कॉलेज दुर्ग में, शहीद भगत सिंह स्कूल तितुरडीह दुर्ग में और रायपुर जिले में शहीद चन्द्रशेखर आजाद जयंती के मौके पर निबंध, स्केच, गीत आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किये गये।

शहीद मदन लाल ढींगड़ा को याद किया

भिवानी (हरियाणा) : यहां 17 अगस्त को स्थानीय नेहरू पार्क में ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) की तरफ से आजादी आन्दोलन की समझौताहीन धारा के महान् क्रान्तिकारी मदन लाल ढींगड़ा के 107वें शहादत दिवस के अवसर पर यादगार सभा की गई। सभा की अध्यक्षता संगठन के राज्य सचिव बलवान ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) के राज्य कमेटी सदस्य कॉ. राजेन्द्र सिंह रहे। सभा का संचालन डी.वाई.ओ. के जिला सचिव कॉ. सन्दीप मेहरा ने किया।

शहीद मदन लाल ढींगड़ा के जीवन-संघर्ष और क्रान्तिकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कॉ. राजेन्द्र सिंह ने बताया कि मदनलाल ढींगड़ा ने उन ब्रिटिश अधिकारियों से बदला लेने का विचार किया जिन्होंने भारत में जनता पर शोषण-जुल्म किये थे। इन्हीं में कर्जन वायली नामक ब्रिटिश अधिकारी था जो उस समय ब्रिटेन के भारत सचिव के सलाहकार के पद पर था। 1 जुलाई, 1909 को इण्डियन नैशनल एसोसियेशन के वार्षिक उत्सव में जब कर्जन वायली लंदन की इम्पीरियल इंस्टिच्यूट के जहांगीर हाल में भाग लेने आये तो मदनलाल ढींगड़ा ने उन्हें अपनी पिस्तौल से गोलियों से भून दिया और इस तरह भारतीय जनता के अपमान का बदला लिया। उन्हें 17 अगस्त के दिन फांसी हुई थी।

संगठन के राज्य संयोजक कॉ. सुमेर सिंह ने बताया कि आज आजादी आन्दोलन के महान क्रान्तिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से भुलाया जा रहा है क्योंकि शहीद मदनलाल ढींगड़ा व अन्य हजारों क्रान्तिकारी देशभक्तों की कुर्बानियों की बदौलत इस देश को आजादी मिली। परन्तु उन शहीदों ने जिस शोषणहीन समाज बनाने का सपना देखा था वह आज भी अधूरा है। आज देश में भीषण शोषण-जुल्म जारी है, धनी लोग गरीबों की मेहनत को लूट रहे हैं। हर तरह के प्रचार-प्रसार के माध्यमों से अश्लीलता परोसकर और नशाखोरी को बढ़ावा देकर लोगों, खासकर युवाओं का नैतिक पतन किया जा रहा है ताकि वे इस शोषण-अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े न हों। उन्होंने कहा कि नीति-नैतिकता के संकट में आज युवाओं को मदन लाल ढींगड़ा जैसे क्रान्तिकारियों के जीवन-चरित्र और जीवन-संघर्ष से प्रेरणा लेनी होगी और युवा आन्दोलन को मजबूत करना होगा। सभा में रजत जांगड़ा, कमल, पवन, राजेश, विशाल, पवन, दिलबाग, पूजा, विकास, प्रीतम, सोनू, राजकुमार, कुलदीप, सतीश, राजेन्द्र, जयवीर आदि अनेक युवा शामिल हुए।

बरसात जनित बीमारियों की रोकथाम व साफ-सफाई की मांग पर प्रदर्शन

दिल्ली : साफ-सफाई, मच्छरों को मारने की दवा छिड़कने, डेंगू का प्रकोप रोकने आदि समस्याओं पर 10 अगस्त को एसयूसीआई (सी) की रामपुरा इकाई द्वारा स्थानीय विधायक के कार्यालय प्रदर्शन किया। दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जितेन्द्र सिंह तोमर को एक मांग पत्र भी सौंपा। प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व एसयूसीआई(सी) त्रिनगर की इंचार्ज कॉ. प्रकाश देवी ने किया। प्रेमराज सैनी, नीतू सैनी, प्रोमिला सैनी, जुगल आदि प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे।

विधायक श्री जितेन्द्र सिंह तोमर को मांगपत्र सौंपते हुए एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

स्मृति दिवस 5 अगस्त

संयुक्त जनआन्दोलन गठित करने का किया आह्वान

(पृष्ठ 4 का शेष)

को बचा सकते हैं। एआईडीवाईओ की महासचिव और पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी की सदस्य कॉ. प्रतिभा नायक भी सभा में उपस्थित थी।

बड़ोदरा (गुजरात) : गुजरात राज्य सांगठनिक कमेटी द्वारा सर्वहारा के महान नेता तथा एसयूसीआई(सी) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर यहां एक स्मृति सभा की गई। इसकी अध्यक्षता पार्टी की राज्य सांगठनिक कमेटी की सदस्य कॉ. मीनाक्षी जोशी ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) की केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. छाया मुखर्जी थी। पार्टी की गुजरात राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य कॉ. तपन दासगुप्ता ने सभा में उपस्थित सभी का स्वागत किया और बताया कि कॉमरेड शिवदास घोष ने उन्नत नीति-नैतिकता के आधार पर क्रान्तिकारी आन्दोलन गठित करने पर बल दिया था। राज्य सचिव कॉ. द्वारकानाथ रथ ने गुजरात के उना में दलितों पर हुए अत्याचारों की घोर निन्दा की। राज्य में एसयूसीआई(सी) बनाना निहायत जरूरी है बावजूद इसके कि सीपीआई यहां मौजूद है। उन्होंने कहा कि अपनी शुरूआत से सीपीआई एक सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी। उन्होंने जनजीवन की समस्याओं को लेकर सरकार की जनविरोधी नीतियों और अघोषित फासीवादी सत्ता के खिलाफ जनआन्दोलनों में हिस्सा लेने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता कॉ. छाया मुखर्जी ने भारत की सरजमीं पर एकमात्र सही कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई(सी) के निर्माण में कॉमरेड शिवदास घोष के महत्वपूर्ण योगदानों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के शुरूआती दिनों से ही कॉमरेड शिवदास घोष आजादी आन्दोलन में कूद पड़े थे। वे जब जेल में थे तो उन्हें यह अहसासा हुआ कि एक सही क्रान्तिकारी पार्टी की अनुपस्थिति में आजादी आन्दोलन की तमाम कुर्बानियों का फल बुर्जुआ वर्ग द्वारा हथिया लिया जाएगा। उन्होंने अपने चंद मुट्ठीभर सहयोद्धाओं के साथ मिल कर बहुत ही कष्टसाध्य संघर्ष चलाकर एसयूसीआई(सी) का निर्माण किया। कॉमरेड शिवदास घोष ने ही हमें पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति की दिशा प्रदान की है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर तरह से एसयूसीआई(सी) को मजबूत बनाएं ताकि पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति का कार्य पूरा हो सके। यह समय का तकाजा है। यही कॉ. शिवदास घोष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

तिरुवल्ला (केरल) : एसयूसीआई (सी) की केरल राज्य कमेटी द्वारा यहां कॉमरेड शिवदास घोष स्मृति सभा का आयोजन किया गया। सभा की मुख्य वक्ता थी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. छाया मुखर्जी।

कटक (उड़ीसा) : एस.यू.सी.आई. (सी) की उड़ीसा राज्य कमेटी द्वारा कॉमरेड शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर 7 अगस्त को कटक के शहीद भवन में एक राज्य स्तरीय सभा की गई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के उड़ीसा राज्य सचिव कॉ. धुर्जटी दास ने की। सभा के मुख्य वक्ता थे एस.यू.सी.आई.(सी) के केंद्रीय कमेटी सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव कॉ. सोमेन बोस। सभा की शुरूआत में पार्टी की किशोर वाहिनी कॉम्सोमोल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

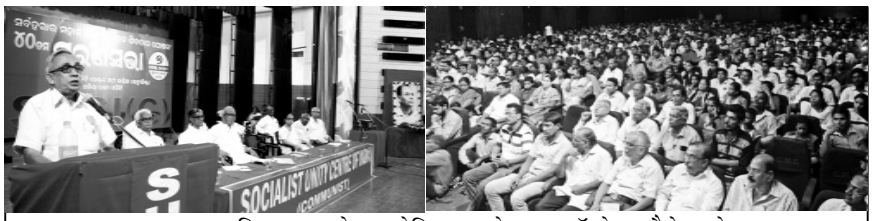

कटक : स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सौमेन बोस

कॉ. सौमेन बोस ने अपने भाषण में कहा कि आज का दिन हम कॉमरेड शिवदास घोष की मूल्यवान सीखों को नये सिरे से जानने और समझने के लिए मनाते हैं। हम शोषित-पीड़ित जनता को शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इसके लिए संघर्ष को तेज करने की शपथ दोहराते हैं।

बुढ़लाडा (पंजाब) : सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर यहां एक स्मृति सभा की गई। इसकी अध्यक्षता पार्टी की पंजाब यूनिट के इंचार्ज कॉ. अमीन्द्रपाल सिंह ने की। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी) की म.प्र. राज्य कमेटी के सचिव कॉ. प्रताप सामल थे। उन्होंने कहा कि कॉ. शिवदास घोष ने अहसास किया किं एसयूसीआई(सी) बनाना निहायत जरूरी है बावजूद इसके कि सीपीआई यहां मौजूद थी लेकिन अपनी शुरूआत से ही सीपीआई एक सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, ठोस हालात का ठोस विश्लेषण न कर पाने से इसने बार-बार ऐतिहासिक गलतियां की। कॉमरेड शिवदास घोष ने भारत की एक सही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करके एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। पार्टी राष्ट्रीय- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सभा का संचालन कॉ. जगतार सिंह ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि पूंजीवाद ने जनजीवन को बेहद दयनीय और दमघोंटू बना दिया है। अगर किसानों की बात करें तो उन्हें हमेशा घाटे का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कॉ. शिवदास घोष के विचारों की रोशनी में ही वर्तमान राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ठीक से समझा जा सकता है।

सागर(म.प्र.) : कॉमरेड शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर 5 अगस्त को सागर में राज्य स्तरीय स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों, पार्टी समर्थक-हमदर्दों और भोपाल, सागर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, देवास, विदिशा, रायसेन आदि जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभास्थल के साथ ही रवीन्द्र भवन में कॉमरेड शिवदास की शिक्षाओं पर एक सुसज्जित उद्धरण प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन पार्टी के राज्य कार्यालय सचिव कॉ. यू.पी. विश्वास ने किया। सभा की अध्यक्षता एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) म.प्र. राज्य कमेटी सदस्य कॉ. रामोवतार शर्मा ने की। सभा के मुख्य वक्ता थे एस.यू.सी.आई. (सी) के उ.प्र. राज्य कमेटी सदस्य कॉ. स्वपन चटर्जी। उन्होंने कहा कि केवल हमारे देश के ही नहीं बल्कि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन का राह रोशन करने वाली हैं कॉमरेड शिवदास घोष की सीखें। उनका बेजोड़ जीवन-संघर्ष प्रेरणादायक है। कॉमरेड शिवदास घोष चिंतन को जानने और जीवन में अपनाने और उन्नत सर्वहारा संस्कृति व नैतिकता हासिल करने की जरूरत पर बल दिया ताकि अच्छा कम्युनिस्ट बना जा सके। पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जनआन्दोलन गठित करने की पुरजोर अपील की।

सागर : स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड स्वपन चटर्जी

देहरादून(उत्तराखण्ड) : एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) की उत्तराखण्ड इकाई द्वारा कॉमरेड शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर 7 अगस्त को देहरादून के पंचायती मंदिर में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के कॉमरेड मुकेश सेमवाल ने की। सभा के मुख्य वक्ता थे एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के म.प्र. राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल। देश में एक सही कम्युनिस्ट पार्टी एसयूसीआई(सी) को बनाने में कॉमरेड शिवदास घोष के बेजोड़ संघर्ष पर उन्होंने चर्चा की। केन्द्र में बीजेपी के शासन के चलते बढ़ते फासीवादी हमलों के खिलाफ संयुक्त वामपंथी आन्दोलन की जरूरत पर उन्होंने बल दिया।

कोलकाता, घाटशिला, बैंगलोर, मदुराई, अगरतला, आदि कई और जगहों पर भी कॉमरेड शिवदास घोष स्मृति सभाएं आयोजित की गई जिनकी खबरें अभी आई नहीं हैं। उनके आ जाने पर शेष खबरें अगले अंक में प्रकाशित की जायेंगी।

तिरुवल्ला : स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड छाया मुखर्जी

देहरादून : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड प्रताप सामल

जीएसटी....

(पृष्ठ 3 का शेष)

भी अधिक सत्तानायक बड़े व्यवसायी को अनुचित, अनैतिक कर छूट एवं संग्रहण में आवश्यक ह्रास को प्रोत्साहित करते हैं तथा स्वेच्छाचारी बड़े दोषी को अकथनीय कर मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए जिस बहाने की आड़ में निर्णय लिया जाता है वह करोड़ों के पॉकेट को और अधिक कंगाल बनाएगा। वे पूँजीवादी शोषण की चक्की में पीसे जाएंगे। अप्रत्यक्ष करों के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाने की यह दलील थोथी ही नहीं बल्कि आपराधिक धोखा भी है। पूँजीवादी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण की निर्देशिका लागू होने के बाद वैट उसी नीति को ध्यान में रखकर लाया गया था ताकि अप्रत्यक्ष कर वृद्धि के सम्पूर्ण भार को सर्वसाधारण के कंधों पर लादने के लिए बाध्य किया जाए। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्मित राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त कमेटी जिसके कन्वीनर तब के पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) के वित्त मंत्री असिम दासगुप्ता थे उनके द्वारा 17 जनवरी 2005 को जारी श्वेत पत्र की प्रस्तावना में दावा किया गया था कि वैट वर्तमान कर जैसे टर्नओवर टैक्स, बिक्री कर पर सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज, विशेष अतिरिक्त कर आदि के तमाम बोझ को समाप्त कर देगा। वैट टैक्स अनुपालन को बेहतर करेगा, राजस्व विकास में वृद्धि करेगा तथा इस प्रकार साधारण जनता, व्यापारी, उद्योगपति तथा सरकार को भी फायदे होंगे। वैट को लागू करने के समय यह तर्क दिया गया कि वैट इस समय के प्रचलित टैक्स पर टैक्स या दुहरा कर प्रणाली को वितरण कड़ी में प्रत्येक स्तर पर लिये जाने वाला टैक्स से मुक्ति प्रदान करता है। वास्तव में CENVAT क्रेडिट योजना (पहले MODVAT से जाना जाता था) जो 2004 में लागू हुआ था जिससे प्रारम्भिक स्तर पर किया गया उत्पाद शुल्क भुगतान को सामान के निकलने पर एक्साइज़ का दायित्व के विपरीत इसे मुक्त कर दिया गया। जी.एस.टी. में समान तर्क को अतिरिक्त बाजीगरी के साथ नई बोतल में पुरानी शराब की तर्ज पर बहुकर के बदले एकमात्र कर लागू किया गया है।

वैट जनता के लिए कोई राहत लाया या उसके बेबसी को तीक्ष्ण किया? सर्व-साधारण जनता का अनुभव क्या है? कोई भी वादे या आश्वासन सच साबित हुए? अलबत्ता संकटग्रस्त क्षयोन्मुख मरणासन्न पूँजीवादी व्यवस्था में अवश्यम्भावी पूर्ण रूप से भ्रष्ट टैक्स प्रशासन को दुरूस्त करने की किसी भी पहल की गैरमौजूदगी ने प्रक्रियागत जोखिम को बढ़ाकर भ्रष्टाचार को केवल आगे ही बढ़ाया है। करदाता की परेशानियों को तीव्र किया है। जो फिर भ्रष्ट प्रशासन के साथ धूर्तता से कर चोरी व टालमटोल के लिए बाध्य होता है। इसके विपरीत वैट वस्तु एवं सेवा के आधार मूल्य पर जोड़ा जाता है तथा अंतिम उपभोक्ता उसे आखिरी मूल्य का अंश के रूप में भुगतान करता है। आगत कर (इनपुट टैक्स) का सही तरीके से तथाकथित समायोजन के तमाम दावे अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने के लिए आम आदमी को निचोड़ने का अगर धूर्ततापूर्ण दाँव नहीं तो बकवास जरूर साबित हुआ। परिणामस्वरूप जनता के जीवन को तबाह करने वाली मूल्य वृद्धि पर स्पष्ट है कि एकाधिकार घराने वैट लागू करवाने के लिए इतने आतुर क्यों थे और कैसे उनकी सेवादार सरकार के साथ-साथ मंत्री-राजनीतिज्ञ-अर्थशास्त्री एक तोहफे के तौर पर इसका ढिंढ़ोरा पीट रहे थे। हमने विश्लेषण कर विस्तार से बताया था कि कैसे वैट के लागू होने से कठिनाइयाँ बढ़ेंगी तथा इसका सारा भार आम जनमानस पर पड़ेगा क्योंकि अन्ततोगत्वा जारी मुद्रास्फीति का अतिरिक्त भार अंतिम मूल्य पर आम उपभोक्ता के कंधों पर डाला जाएगा। जनता अब अनुभव से पता कर सकती है हमार विश्लेषण तथा निष्कर्ष जो मार्क्सवादी प्रक्रिया आधारित था, कितना सही था! वैट का अनुभव दुनिया में सभी जगह समान रूप से विनाशकारी रहा। वैट को लागू करने के समय इस मॉडल के समर्थक कह रहे थे कि बहुत सारे देशों में वैट श्रमिकों के लिए सकारात्मक रहा है। ब्राजिल देश का उदाहरण दिया गया था किनतु आज ब्राजील की अर्थव्यवस्था अत्यधिक महंगाई से पूर्णत: नष्ट होने के कगार पर है।

सीख यह है कि अगर कोई पूँजीवाद के बुनियादी नियम से अलग किसी आर्थिक नवीनीकरण या राजस्व संबंधी सुधार या कर प्रणाली में परिवर्तन कर यह आजमाने की कोशिश करता है कि कर सुधार के माध्यम से लोगों को सम्भावित राहत मिलेगी तो वह इस बारे में एक बेबुनियाद अनुमान के भ्रमजाल का शिकार हो जाएगा। दूसरा वैट के प्रश्न पर भी पूँजीवादी दुनिया के आर्थिक नीतिनिर्माताओं के बीच मतभेद रहे हैं। वैट विरोधी खेमे का तर्क है कि वैट मुक्त देशों की तुलना में वैट युक्त देश में कुल टैक्स बोझ अत्यधिक है। विडम्बना है कि इसी तरह के तर्क के साथ वैट लागू करने वाले प्रवर्तक यूरोपीय यूनियन के शासक एकाधिकारी जिसे भारतीय पुछल्ला एक दशक बाद लाया, ढिंढ़ोरा पीटने वाली यूरोपीयन यूनियन आज न केवल आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है बल्कि इसके पूरे अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस आर्थिक ह्रास को वैट के मत्थे मढ़ दें। बल्कि यह दिखाता है कि वैट हो अथवा न हो, जहाँ तक समस्त आर्थिक गतिविधि तथा आमजन की आर्थिक बदहाली सुधरने का ताल्लुक है कोई फर्क नहीं पड़ता है।

जी.एस.टी. का नतीजा भी बहुत बुरा नहीं तो कुछ अलग नहीं होगा। हमें विश्वास है कि वैट के संदर्भ में उपयुक्त संक्षिप्त चर्चा जी.एस.टी. के प्रपंच को समझने में मदद करेगी। अब तक दुनिया में 160 देशों में जी.एस.टी. या वैट है। फ्रांस पहला देश था जो 1954 में वैट लागू किया। किस प्रकार वहाँ आम आदमी लाभान्वित हुआ? क्या टैक्स का बोझ कम हुआ? क्या महंगाई कम हुई? निस्संदेह जवाब बेहद नकारात्मक होगा। उल्टे जी.एस.टी. ने व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद की। इस बात से भिन्न कि एकसमान टैक्स नुस्खा के रचयिता का गणितीय दावा क्या रहा है। सबसे पहले तो जैसे कि पहले कहा जा चुका है जी.एस.टी. एक आपूर्ति आधारित टैक्स है। जी.एस.टी. की वकालत करने वाले का तर्क है कि इसका अभिप्राय उत्पादन टैक्स की बजाय उपभोग टैक्स से है। क्योंकि एक आदमी एक वस्तु या सेवा का उपभोग अपनी मर्जी से करता है इसलिए टैक्स उसे ही वहन करना है। ये दावा करते हैं कि आयकर या प्रत्यक्ष कर में कोई बचतकर्ता हो या उपभोगकर्ता हो उससे पृथक वह दंड भुगतान है। किन्तु उपभोग अवधारणा में एक को टैक्स तभी भरना पड़ता है जब वह उपभोग करता है जो उसके मर्जी पर निर्भर करता है। यही पकड़ने का बिन्दु है या प्रतिज्ञप्ति का मूल है। जब एक पूँजीवादी विनिर्माता या निवेशक अत्यधिक मुनाफे के लिए वस्तु व सेवा विनिर्माण करता है तब वह दण्डित नहीं होता है किन्तु एक आम आदमी अपना जीवन यापन करने मात्र के लिए उपभोग करता है तो वह दण्डित होना चाहिए। इस प्रकार के भ्रान्त तर्क का मरणासन्न पूँजीवाद में बुर्जुआ अर्थशास्त्री के शब्दकोष में ही स्थान मिलता है। आज एक ब्लॉगर इन्टरनेट पर सेल फोन की बिक्री का दो तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्य से उनके लिए वह चार्ट संलग्न सच्चाई को खोल देता है (द्वारा: quora.com)

अगर कोई सावधानी से गौर करे। जी.एस.टी. सिस्टम में वितरक ज्यादा मुनाफा बनाते पाया जाता है। जी.एस. टी. चालान में सामान का बिक्री मूल्य 17,400 रुपये है जबकि जी.एस.टी. मुक्त सिस्टम में यह 15,600 रुपये है। साधारण बुद्धि कहती है कि बाजार में अंतिम उपभोक्ता या साधारण खरीदार अंत में अधिक मूल्य चुकाएगा। वैट के साथ आज क्या हो रहा है। संपूर्ण 15% का भार एकमुश्त टैक्स घटक अंतिम मूल्य पर जुड़ता है। तथा खरीदार को इसे जाँचने का कोई मौका नहीं होता है कि आगत-कर क्रेडिट (ITC) है या नहीं अथवा दुहरा कर से मुक्त है या नहीं। जी.एस.टी. के साथ भी वही प्रक्रिया काम करेगी। भूल जाएँ, कि वितरण कड़ी में कौन किस स्तर पर कितना टैक्स भरा है।

एक समीक्षक ने आशंका व्यक्त किया कि सेवाएँ जिसमें अभी 15% टैक्स मौजूद है वह महँगी हो जाएगी क्योंकि जी.एस. टी. दर 18-22% या उससे अधिक होने वाली है। इसके अतिरिक्त सरकार की यह आदत रही है कि बाद में किसी पर कभी भी सेस लादकर वर्तमान अप्रत्यक्ष कर दर का भारी बोझ लादा है। हाल के दिनों में स्वच्छ भारत सेस तथा कृषि कल्याण सेस लादा गया है। यह साफ नहीं कि जीएसटी सिस्टम में भी यह सेस जारी रहेगा तथा जनता का खून और अधिक निचोड़ा जाएगा।

एशियाई देशों में जीएसटी का अनुभव

शासकों का जितना भी दावा रहा हो वैट की तरह जीएसटी दूसरे देशों में जनता के लिए विपत्ति भरा साबित हुआ है। ऐसी सूचना मिली है कि मलेशिया में आम आदमी, खासकर श्रमिक जनता जीएसटी के लागू होने से पीड़ित है। इसके परिणामत: श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया में मूल्य वृद्धि हुई है। जीवन के रोजमर्रा की हरेक चीज अधिक महंगी हो गई। एक दूसरा मलेशियन शहर पेनांग में खुदरा दुकान जो 45 वर्षों से चल रही थी बंद हो गई क्योंकि उसके मालिक जीएसटी जटिलता के साथ तालमेल नहीं बैठा सके तथा वह लेखाकार का वहन करने में असमर्थ हो गए। दूसरा जीएसटी के अमल के साथ व्यापारी आराम से ऊँची कीमत को उपभोक्ता पर फेंक देंगे जो अन्ततोगत्वा हानि भुगतने वाला होगा। वे जो निम्न आय-समूह में हैं उन्हें अंत में वहन करना मुश्किल हो जाएगा तथा कुछ के लिए चोरी व डकैती अंतिम चारा रह जाएगा तथा परिणामस्वरूप सामाजिक समस्या बढ़ जाएगी। (मलेशियन-चाईनिज समाचार डॉट कॉम, दिनांक 31 मार्च 2015)

भारत सरकार जीएसटी लागू करने में इतनी उत्सुक क्यों है- स्वाभाविक है किं कोई भी प्रश्न पूछने के लिए विवश होता है कि फिर जीएसटी क्यों? जवाब साधारण है। यह भारतीय एकाधिकारी पूंजीपतियों की वर्ग जरूरत है। जैसा जान पड़ता है जहाँ तक टैक्स गणना के प्रक्रियागत जोखिम का सवाल है, इसका उद्देश्य कर प्रणाली को केन्द्रित कर औद्योगिक घरानों, कॉर्पोरेट जम्बो तथा बड़े व्यापार को राहत देना है। जीएसटी के रूप में अपेक्षाकृत वे एक समायोजित टैक्स भरेंगे तथा जारी सेवा कर या वैट की तरह इसे बिक्री मूल्य पर चढ़ाकर आसानी से अंतिम उपभोक्ता से वसूल लेंगे। यह टैक्स विवाद के प्रकरण को कम करेगी, खासकर विदेशी कम्पनी जो भारतीय बाजार में एफडीआई या ज्वाइंट-वेन्चर के तहत धावा बोल रही हैं। वास्तव में विदेशी एकाधिकारी घराने भी टैक्स नियमों के सरलीकरण को माँग उठा रहे हैं ताकि भारतीय व्यापार में अधिकतम मुनाफा उत्पन्न करने तथा प्रत्यावर्तन के सामने कोई बाधा न हो। खासकर वे रक्षा, खुदरा व्यापार, दवाई, पढ़ाई तथा वित्तीय क्षेत्रों में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ही हाल के एफडीआई मानक का उदारीकरण के बाद जीएसटी के लिए दबाव बनाया है। यह भारतीय एकाधिकारी शासक के द्वारा समान रूप से इच्छित है जो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। वे घरेलू व्यवसाय में सभी तरह के अवसर के लाभ के अतिरिक्त अपने बाहरी व्यापार में विदेशी पूँजी को समान फायदा लाने वाला बनाना चाहते हैं। इसलिए ये तमाम योजना जनहित के विरुद्ध है तथा इसे शोषणमूलक बुर्जुआ शासन के वर्ग-हित की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

जीएसटी का जनविरोधी चरित्र किसी विपक्षी दल ने रेखांकित नहीं किया। यहाँ गौरतलब है कि कुछेक द्वारा शुरूआत में किये गये हल्के-फुल्के विरोध को छोड़कर कोई भी दल नहीं है जिसने जीएसटी के बारे में इस तरह से प्रश्न उठाये हों कि यह जनता के हित के विपरीत है। इनका सारा विरोध राज्य को मिलने वाले जीएसटी राजस्व के हिस्से का प्रतिशत तथा राज्य को कोई राज्य विशेष कर लगातर अतिरिक्त राजस्व लेने के अधिकार आदि तक ही सीमित था। सी.पी.आई.(एम) की नाराजगी भी केवल इतनी भर थी कि संसाधन जुटाने का जो कुछ भी थोड़ी बची-खुची शक्ति राज्य सरकार के पास है जीएसटी के कारण वह भी छिन जाएगी। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपदा होने पर या जनता के जीवनयापन की बेहतरी के लिए कल्याणकारी योजना की राशि के लिए राज्य सरकार को अब केन्द्र सरकार की दया पर निर्भर रहना होगा तथा ऐसे में राज्य को मुआवजा देने की प्रक्रिया जो अपना राजस्व जीएसटी के लागू होने से खो चुकी होगी, उसे ठीक तरह से देखना पड़ेगा। अभी केरल के सी.पी.आई.(एम) मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीएसटी पर उनका कोई विरोध नहीं है। यह समझा जा सकता है कि जनता द्वारा वहन को लेकर शुरूआत में जो थोड़ा रोष व्याप्त था वह समाप्त हो गया है तथा वे भी जीएसटी पर मतैक्य में शामिल हैं तथा आगे जनता के भाग्य पर कालिख पोतने के लिए तैयार हैं।

जनता को प्रतिवाद करना चाहिए

यह स्पष्ट है कि जीएसटी का समायोजित टैक्स प्रणाली बड़े स्तर के आर्थिक सुधार प्रक्रिया का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। भारतीय एकाधिकारी शासक अपने आर्थिक आधार को क्षय होने से बचाने के लिए आर्थिक शक्ति को एकीकृत व केन्द्रीकृत करने का प्रयास कर अपनी अंतिम कब्र खोदने की शुरूआत कर चुका है। यह पूर्ण रूप से हमला नहीं तो गरीबी से आक्रांत, दुख से पीड़ित श्रमिक जनता पर एक अत्यंत कठोर प्रहार साबित होने जा रहा है। भाजपा, आज के सबसे वफादार राजनीतिक प्रबंधक को उसके पूर्ववर्ती कांग्रेस का इशारा लेकर तथा वोट आधारित संसदीय दलों के सत्ता के सौदागरों से सहयोग पाकर इस योजना को आकार देने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इन परिस्थितियों के बीच जनता के पास चेतनायुक्त प्रतिवाद उठाने तथा इन राक्षसी आर्थिक सुधार के खिलाफ फौरन सही नेतृत्व के तहत एक संगठित दीर्घ शक्तिशाली आंदोलन निर्मित करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह एस.यू.सी.आई.(सी) है जो मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन के उच्च आदर्शों से संचालित है जो जीएसटी पर उपयुक्त विश्लेषण प्रस्तुत किया है जो जनहित की रक्षा हेतु एकमात्र चरित्र होने का दावा कर सकती है। हम जनता का आह्वान करते हैं कि वे आगे आएँ। सच्चाई को समझें तथा जीएसटी एवं दूसरे सुधार कार्यक्रम के पीछे घृणित मंशा को बेनकाब करें। ●●●

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7-8 and 22-23 Fortnightly , Date of Publication : August 20, 2016
सर्वहारा दृष्टिकोण
22 अगस्त, 2016

सरकार की श्रमिक-कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 सितम्बर की देशव्यापी हड़ताल की तैयारी में हुई महारैली

करनाल (हरियाणा) : केन्द्रीय श्रमिक संगठनों व कर्मचारी फैडरेशनों की ओर से 9 अगस्त को भारत छोड़ो आन्दोलन के दिन करनाल के हुड्डा ग्राउण्ड में आयोजित रैली में हरियाणा के हजारों मजदूर-कर्मचारियों ने हुंकार भरी। मजदूर-कर्मचारी नेताओं ने 2 सितम्बर की देशव्यापी हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का आह्वान किया। महारैली में प्रदेश के कोने-कोने से आये भिन्न-भिन्न क्षेत्र के मजदूर-कर्मचारियों ने शामिल होकर एकजुटता का परिचय दिया। इसमें महिला कर्मचारियों की मौजूदगी उल्लेखनीय थी।

महारैली में इंटक के राज्य अध्यक्ष अमित यादव, एटक के अध्यक्ष बलदेव घणघस, एचएमएस के राज्य अध्यक्ष आरडी यादव, सीटू के प्रदेश महासचिव जयभगवान, एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान, सर्वकर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष धर्मवीर फोगाट, हरियाणा कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष कंवर सिंह यादव, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के राज्य महासचिव सूबे सिंह व एआईबीईए के चेयरमैन एन पी मुंजाल ने सम्बोधित किया। नौ सदस्यीय अध्यक्षमण्डल में धर्मबीर लोहान, बेचु गिरी, पुष्पेन्द्र शर्मा, सतबीर सिंह, नरेश शास्त्री, वीरेन्द्र धनखड़, आर के नागर व नरेश बागड़ी और एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश थे।

वक्ताओं ने मांग की कि न्यूनतम वेतन 18000 रुपये मासिक हो। श्रम कानून लागू हों। ठेका प्रथा समाप्त हो। ठेका-केजुअल-आउटसोर्सिंग व कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। राज्य में नौकरी से निकाले गये मजदूर-कर्मचारियों को बहाल किया जाए। पंजाब के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। लाखों खाली पड़े पदों पर स्थायी भर्ती की जाए। बिजली, रोडवेज, पब्लिक हैल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम सरकारी विभागों, संस्थाओं व संसाधनों का निजीकरण बंद किया जाए। बिजली कर्मचारियों के साथ किये गए समझौतों को लागू किया जाए। भवन निर्माण श्रमिकों को मिलने वाले हितलाभ की प्रक्रिया सरल की जाए। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील समेत सभी स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। खेतमजदूरों, मनरेगा सहित असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को 500 रुपये दैनिक दिहाड़ी व साल भर काम दिया जाए। बैंक, बीमा, रेलवे, रक्षा व अन्य सरकारी विभागों व खुदरा व्यापार में एफडीआई पर रोक लगे। बैंकों का मर्जर बंद हो। पूंजीपतियों द्वारा लिये गए कर्जों को सख्ती से वसूल किया जाए। महंगाई पर रोक लगाई जाए। सभी आवश्यक वस्तुएं सस्ती दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलें। ट्रेड यूनियन आन्दोलन को कुचलना, उस पर एस्मा व पुलिस दमन बंद हो। श्रम कानूनों में मजदूर-विरोधी संशोधन रद्द किये जाएं। सभी मजदूर-कर्मचारियो को ईएसआई, पीएफ व पेन्शन के दायरे में लाया जाए और पुरानी पेन्शन नीति बहाल की जाए। समान काम का समान वेतन व स्थायी कामों में स्थायी भर्ती की जाऐ।

उपस्थित जनसमूह ने केन्द्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 2 सितम्बर की देशव्यापी हड़ताल को सफल करने का संकल्प लिया।

करनाल : मजदूर-कर्मचारियों की महारैली को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान

तुर्की के राष्ट्रपति रिसैप एर्डोगन द्वारा लिए गए कठोर कदमों की अखिल भारतीय साम्राज्यवाद-विरोधी फोरम ने की कड़ी निंदा

अखिल भारतीय साम्राज्यवाद-विरोधी फोरम ने 22 जुलाई 2016 को निम्न बयान जारी:-

अखिल भारतीय साम्राज्यवाद-विरोधी फोरम तुर्की के राष्ट्रपति रिसैप एर्डोगन द्वारा उठाए गए कठोर कदमों की तथा मानवाधिकार यूरोपीय सम्मेलन को स्थगित करके एमरजेंसी लागू करने की घोर निंदा करता है। इससे पहले भी एकेपी सरकार ने लोकतांत्रिक आंदोलनों पर बहुत ही वीभत्स और हिंसक हमले किए हैं। यहां तक कि पत्रकारों को भी नहीं बक्शा गया जो कि घटना को कवर कर रहे होते हैं। अब राष्ट्रपति एर्डोगन 'तख्ता पलटने' के असफल प्रयास को एक बहाना बनाकर सभी विरोधी ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं और हजारों हजार पुलिस अधिकारियों, सेना के जवानों को यहां तक कि बड़े-बड़े जनरलों, जजों, वकीलों, अध्यापकों तथा विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को जेलों में ठूंस दिया है और मीडिया में आ रहे फोटोग्राफों से पता चलता है कि उन्हें कड़ी यातनाएं भी दी जा रही हैं। वास्तव में राष्ट्रपति एर्डोगन सभी विरोधी ताकतों का बहुत ही निर्दयता के साथ सफाया कर देना चाहते है। ताकि उनके विरोध में कोई भी आवाज न उठा सके। तुर्की एक क्रूर फासीवादी निरंकुश शासन स्थापित हो गया है। एआईएआईएफ ने इन कदमों का कड़ाई से विरोध करते हुए तुरंत लोकतंत्र बहाल करने की मांग की है। एआईएआईएफ तुर्की की संघर्षशील जनता के संघर्ष में उनके साथ है।

2 सितम्बर की हड़ताल.!!!

(पृष्ठ 1 का शेष)

मुनाफा कमाने का संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में रिक्त पड़े लाखों पदों पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। कंट्रेक्ट लेबर (रेगूलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट 1970 का उद्देश्य था स्थायी कामों में ठेका मजदूरों की नियुक्ति को घटाते हुए अंततः ठेका प्रथा का उन्मूलन कर देना और मजदूरों की स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित कर देना। अब सरकार इस कानून से एबोलिशन यानी उन्मूलन शब्द को ही हटा देना चाहती है। इसका मायने है स्थायी मजदूरों की बजाये नाममात्र के वेतन-भत्ते पर ठेका मजदूरों को सभी कामों में नियुक्त किया जा सकेगा, जिनके लिए पेन्शन, पीएफ, ग्रेच्यूटी इत्यादी कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं रहेगी।

न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के अनुसार किसी भी क्षेत्र के मजदूरों के लिए इससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि न्यूनतम मासिक वेतन 18000 रुपये से कम नहीं होगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र में इतना वेतन नहीं दिया जा रहा है। महीने में कुल मिलाकर 5 या 6 हजार रुपये पर काम करने को मजबूर है मजदूरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिससे आकाश-छूती महंगाई के इस दौर में परिवार का गुजारा होना नामुमकिन है। सिर्फ प्राइवेट मालिक ही न्यूनतम वेतन कानून का उल्लंघन करते हों, यह बात नहीं है। केन्द्र व राज्य सरकारें भी न्यूनतम मजदूरी कानून का सरासर उल्लंघन कर रही हैं। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील कर्मियों को मिलाकर भारत में इनकी संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है। इनकी नियुक्ति सरकार करती है। लेकिन आज तक इनको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। इनका कोई निश्चित वेतनमान नहीं है। भत्ते या मानदेय के रूप में भिक्षा या खैरात के तौर पर कुछ रुपया इन्हें थमा दिया जाता है। इनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। 'विकास' की दावेदार कांग्रेस, बीजेपी, किसी की भी सरकार ने इनकी समस्या के समाधान के लिए लेशमात्र भी प्रयास नहीं किया है।

देशी-विदेशी एकाधिकारी पूंजीपतियों की मांग है कि 'विकास' करना है तो मजदूरों के पास से कानूनी रक्षा कवच छीन लिया जाए। इसके लिए सरकार 1948 के औद्योगिक विवाद कानून में संशोधन के नाम पर ऐसे बदलाव ला रही है जिनके चलते 90 फीसद औद्योगिक मजदूरों की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं रहेगी। सरकार ने स्माल फैक्ट्रीज(रेगूलेशन ऑफ सर्विस कंडीशन) बिल का प्रारूप तैयार किया है जिसके कानून बन जाने पर अधिकतम 39 मजदूर जहां काम करते हैं ऐसे कारखानों पर 14 प्रमुख श्रम कानून लागू नहीं होंगे। ईपीएफ एण्ड एमपी एक्ट 1952, ईएसआई एक्ट 1948 आदि किसी को भी बाध्यतामूलक रूप से लागू नहीं किया जाएगा।

इन तमाम हमलों के फलस्वरूप मेहनतकश लोगों में विक्षोभ और असंतोष बढ़ेगा, आन्दोलनों के रूप में यह अगर कहीं फूट पड़े, तो उन आन्दोलनों को दबाने के लिए सरकार ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को इस तरह बदल रही है कि मजदूर ट्रेड यूनियन ही न बना सकें।

मेहनतकश लोगों पर इस सर्वव्यापक हमले के खिलाफ अखिल भारतीय पैमाने पर 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम मान्य कार्यक्रम के आधार पर जो आम हड़ताल करने का आह्वान किया है, उसे कार्यकारी बनाने के मामले में श्रमिक संगठन एआईयूटीयूसी हर राज्य में अपनी भूमिका निभा रही है।

12 सूत्री मांगें : 1. श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर मजदूरों के अधिकार छीन कर मध्ययुगीन दास प्रथा लागू करने की साजिश बंद की जाए। 43-46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में सर्वसम्मति से लिये गये फैसलों को तुरंत लागू किया जाए।
2. महंगाई रोकने के लिए आवश्यक कदम तुरंत उठाये जाएं।
3. बेइंतहा बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए। सभी को रोजगार दिया जाए।
4. मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ते हुए न्यूनतम वेतन 18000 रुपये मासिक दिया जाए।
5. सर्वजनीन सामाजिक सुरक्षा दी जाए।
6. आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और पैरा टीचरों सहित केन्द्रीय योजनाओं में नियुक्त सभी कर्मियों को श्रमिक का अधिकार व दर्जा दिया जाए। इन योजनाओं के लिए वित्तीय आबंटन बढ़ाया जाए।
7. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा सहित सभी मेहनतकश लोगों के लिए सेवानिवृति पर सुनिश्चित पेन्शन की व्यवस्था की जाए। हाकरों के लिए बनाये कानून को तुरंत लागू किया जाए।
8. स्थायी कामों में ठेका प्रथा बंद हो। तब तक समान काम का समान वेतन के आधार पर सभी ठेका श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएं।
9. श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए श्रमिकों के अधिकारों को कानूनसम्मत मान्यता दी जाए।
10. केन्द्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में विनिवेश की प्रक्रिया बंद की जाए।
11. बोनस, ईएसआई, पीएफ कानून में योग्यता सीमा समाप्त की जाए। ग्रेच्यूटी की मात्रा बढ़ाई जाए।
12. आवेदन के 45 दिन के अन्दर ट्रेड यूनियन को पंजीकृत किया जाए। आईएलओ कन्वेन्शन नं. 87 और 98 को भारत सरकार मान्यता दे।

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com
फोन नं. : 011-25726631, 9868350503